(ग) सरकार ने वर्ष 1992–93 के दौरान जीवन बीमा निगम के सहयोग से विद्युतकरघा बुनकरों के लिए एक समूह बीमा योजना शुरू की है। इस योजना में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा विद्युतकरघा क्षेत्र द्वारा वार्षिक प्रीमियम की बराबर भागीदारी करने की व्यवस्था है। 10,000 रु० वाले बीमा के लिए 120 रु० का वार्षिक प्रीमियम अदा किया जाएगा। भारत सरकार की निधियों के अंशदान को प्रतिपूर्ति आधार पर राज्य सरकार के जरिए सरणीबद्ध किया जाएगा।

(घ) जी नहीं।

(ङ) इस समय 11.9 लाख विद्युत-करघा पंजीकृत हैं जिनकी क्षमता लगभग 24,000 मिलियन वर्ग मीटर कपड़ा प्रतिवर्ष है तथा जिनका प्रतिशत उपयोग 67 प्रतिशत बनता है।

Export of Cotton

2608. SHRIMATI MIRA DAS :

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH :

SHRI P. UPENDRA :

SHRI MUHAMMAD MASOOD KHAN :

SHRI CHIMANBHAI MEHTA :

Will the Minister of TEXTILES be please to state :

(a) whether it is a fact that carry-over stock of the cotton is likely to be more than 47 lakh bales of cotton at the end of the year;

(b) if so, what are the reasons for which only 5 lakh tonnes of bales have been permitted for exports and not 15 lakh bales at present;

(c) whether Government propose to ask institutional buyers to purchase about 40 per cent of the current year production i.e., around 30 lakh bales to prevent slump in the market and protect farmers' interest; and

(d) whether cotton production in the world is higher than consumption ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT) : (a) No Sir. Cotton Advisory Board (CAB), in its meeting held on 9th October, 1992, has estimated the carry-over stock of cotton at the end of the cotton year 1992-93 at 37.70—42.70 lakh bales.

(b) After evaluating the cotton scenario and in terms of Governments long term strategy regarding export of cotton to help cotton farmers, the Government has pleased 9.26 lakh bales of cotton so far during the current cotton season.

(c) Cotton Corporation of India (CCI) is an organisation which undertakes price support operations on behalf of the Government, as and when the kapas prices fall below the minimum support price levels fixed. CCI's endeavour is to sustain the price level of Kapas. In addition, CCI also undertakes commercial operations in cotton for domestic & export requirements. To protect the farmers' interest, the Government have already released a quota of 9.26 lakh bales for export during the year to CCI and the other Coop. Institutions.

(d) No, Sir. The Cotton production in the world during 1992-93 has been projected at 18.90 million metric tonnes as against the estimated consumption of 19.04 million metric tonnes.

Modernisation of Sick Textile Mills

2609. SHRI SURESH PACHOURI : Will the Minister of TEXTILES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that under the new textile policy Government had earmarked 800 crore rupees for the modernisation of sick textile Mills in the country in 1987;

(b) whether it is also a fact that only fifty per cent amount has been spent so far;

(c) if so, what are the details of amount spent year-wise since 1987 and the reasons for not spending the entire funds earmarked for the purpose; and

(d) what further action Government propose to take for the modernisation of sick Textile Mills in the country and bring them out of red in the near future ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT) : (a) to (d) In pursuance of Textile policy announced by Government of India in June 85, Textile Modernisation Fund Scheme (IMFS), was introduced by Industrial Development Bank of India (IDBI), in 1986 with a view to extending financial assistance for modernisation of textile mills through replacement/renovation of equipment/machinery, upgradation of technology, improvement of product quality and enhancement of export capability. TMF, set up with a corpus of Rs. 7.50 crore was intended to be utilised over a period of 5 years (1986—91). As on Aug. '92 an amount of Rs. 853.25 crore has been disbursed under the scheme. The amount disbursed to Textile Mills since 1987 is given below :—

(Rs. in crore)

Year	Disbursed
1987-88 (July-June)	179
1988-89 (July-June)	174
1989-90 (July-March)	174
1990-91 (April-March)	141
1991-92 (April-March)	119
1992-93 (Till April)	6

हुकुमचन्द मिल, इन्दौर का बन्द होना

2610. **श्री गया सिंह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में इन्दौर की हुकुमचन्द मिल पिछले एक वर्ष से बन्द पड़ी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मिल को फिर चालू करने के लिए क्या योजना बनाई है; और

(ग) इस मिल के स्थायी रूप से बन्द हो जाने की स्थिति में कितने मजदूरों के बेकार हो जाने की संभावना है और उनके लिए क्या वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराए जाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) ने मिल को गैर-अर्थक्षम पाया है तथा तदनुसार उसे बन्द करने की सिफारिश की है । तथापि, प्रबन्धकों ने ए० ए०आई० एफ० आर० के समक्ष अपील की है । ऐसा सूचित किया गया है कि इस मिल में प्रभावित होने वाले संभावित कामगारों की संख्या 5659 है ।

गया काटन एवं जूट मिल के लिए कच्चे माल की कम आपूर्ति

2611. **श्री गया सिंह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया काटन एण्ड जूट मिल्स को आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति उसकी मांग की तुलना में काफी कम हो गई है ;

(ख) उपर्युक्त मिल की मशीनों के आधुनिकीकरण के लिए क्या योजनाएं हैं;

(ग) क्या यह सच है कि मिल के प्रबन्धकों द्वारा उसकी मशीनों और भूमि की बिक्री की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां । कार्यशील पूंजी की घोर कमी के कारण गया काटन तथा जूट मिल्स सहित एन० टी० सी० की अधिकांश मिलों में कच्चे माल की सप्लाई उनकी आवश्यकता से कम है ।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ निरंतर घाटे होने, कम उत्पादकता, अधिक मानव